

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती रुबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :-384/2024

निर्णय दिनांक :-26.02.2026

उनवानी दावा:

ललता पत्नि परमेश्वर पुत्री घासीलाल जाति ब्राहमण निवासी बंधली तहसील
दूनी जिला टोंक राज0

-प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाश पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी बंधली तहसील दूनी
जिला टोंक राज0
2. सीताराम पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण जाति ब्राहमण निवासी बंधली तहसील दूनी
जिला टोंक राज0

-अप्रार्थीगण-

-उपस्थिति -

श्री प्रेमचन्द जैन

अधिवक्ता अधि0प्रार्थीगण

श्री अनिल भूरेठा

अप्रार्थीगण सं 1 ता 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिटनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसके डिक्री होन की पूरी सम्भावना है, प्रार्थना पत्र के तीनों तत्व प्रार्थीया के पक्ष में साबित हैं। आ0 ख0 नं0 1569 रकबा 0.0900 है0 ग्राम बंधली तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है, जिसकी प्रार्थीया एक मात्र रिकार्डेड खातेदार तथा खाबिज महिला काश्तकार है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है तथा काश्त कर उसकी पैदावार का उपयोग-उपभोग कर जीवन यापन कर रही है, जिसका प्रार्थीया को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित भूमि से प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी का या प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध या लेना देना किसी प्रकार का नहीं है, प्रार्थीया एक महिला खातेदार, काश्तकार है तथा प्रतिपक्षीगण पुरुषवर्ग बदमाश व झगड़ालू किश्म के लोग हैं जो बिना किसी अधिकार के ताकत के बल पर कानून को अपने हाथ में लेकर प्रार्थीया को असहाय समझकर, जबरन उक्त भूमि से बेदखल करने प्रार्थीया के कब्जे-काश्त में हस्तक्षेप करने तथा स्वयं नाजायज रूप से कब्जा करने पर आमादा है इस कारण उनको दावे के निर्णय तक रोका जाना आवश्यक है। प्रतिपक्षीगण को दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करना आवश्यक व न्यायसंगत है कि वे स्वयं जरिये नौकर चाकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करे। इसको बेदखल या स्वयं नाजायज कब्जा नहीं करे अन्यथा प्रार्थीया को अपार हानि होगी। कई प्रकार के

Rubiy

व शांतिभंग होगी तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी प्रतिपक्षीगण अपने नाकाम
बो में सफल हो जायेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर
बिदन है कि प्रतिपक्षीगण को दावे के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद
करना आवश्यक व न्यायसंगत है कि वे स्वयं जरिये नौकर चाकर रिश्तेदार या अन्य
किरीसी के माध्यम से प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित वादग्रस्त
भूमि आ० ख० नं० 1569 रकबा 0.0900 है० ग्राम बंधली तहसील दूनी जिला टोंक में
प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करें। इसको
बेदखल या स्वयं नाजायज कब्जा नहीं करें

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता अनिल भूरेडा ने
वकालतनामा पेश किया व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है— प्रार्थना पत्र का चरण
नम्बर 1 में वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष इबारत गलत है, स्वीकार
नहीं है। प्रार्थीया के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय
क्षति नहीं है बल्कि प्रतिपक्षीगण के पक्ष में सिद्ध है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 में
वर्णित आराजी भूमि की प्रार्थीया खातेदार होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थना पत्र में वर्णित
आराजीयात पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में
काबिज है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में
वर्णित आराजीयात पर प्रार्थीया कभी भी काबिज नहीं रही है। प्रतिपक्षीगण का शुरु से
ही प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में
भी प्रतिपक्षीगण भूमि पर काबिज है। प्रार्थीया के पिता घीसालाल की मृत्यु सन 2005 में
हो चुकी है तथा प्रार्थीया का विवाह लगभग 30-35 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा प्रार्थीया
अपने ससुराल में निवास कर रही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से
वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का जब भूमि पर कब्जा ही
नहीं है तो प्रार्थीया को भूमि से बेदखल करने, कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने तथा
नाजायज कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थीया के पिता व प्रतिपक्षीगण के
पिता व नाथूलाल भाई थे। पूर्व में उक्त जमीन सिवायचक थी जो बाद में प्रार्थीया के
बड़े पिता नाथूलाल के खातेदारी में लगा दी गई। प्रार्थीया का कभी भी उक्त भूमि पर
कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है
गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का कभी भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा
नहीं रहा है और ना ही प्रार्थीया वर्तमान में काबिज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड
में गलत रूप से बतोर खातेदार अंकित है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया,
प्रतिपक्षीगण को इस वाद व प्रार्थना पत्र की आड़ में मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त
भूमि से बेदखल करना चाहती है जिसका कि उसे कोई कानूनी व वैधानिक अधिकार
प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र में चाही गयी प्रार्थना गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया कोई
अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रहा है। प्रार्थीया का कभी भी प्रार्थना पत्र में
वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है और ना ही प्रार्थीया वर्तमान में काबिज है।
प्रतिपक्षीगण वर्तमान में उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे हैं इस कारण
प्रतिपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि

Pulley

गण को पाबंद कर दिया गया तो प्रतिपक्षीगण को नाकाबिले नुकसान होगा तथा जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रा०पत्र के तथ्यों को ही दोहराया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।


अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 ता 2 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संम्वत 2074-77 वाके ग्राम बंधली पटवार हल्का बंधली तहसील बंधली में ललता पत्नी परमेश्वर पिता घासीलाल जाति ब्रह्मण के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किसी भी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की स्वीकृति हेतु तीन मूलभूत सिद्धांतों का होना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला कब्जा सम्बन्धी विवाद प्रार्थीया ने स्वयं को काबिज बताया है, राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना मात्र ही मौके पर भौतिक कब्जे का पूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक कि मौके की स्थिति स्पष्ट न हो। यह निर्विवाद है कि रिकॉर्डेड खातेदार का कब्जा स्वतः माना जाना चाहिए, किन्तु अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का लम्बे समय से कब्जा है जो कि साक्ष्य का विषय है। बिना साक्ष्य/सबुतों के प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण का तर्क है कि वे मौके पर खेती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, बिना गहन साक्ष्य के, उन्हें वर्तमान स्थिति से बेदखल करने या पाबंद करने से खेती के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, जिससे सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि विवाद विषय कब्जा है और साक्ष्य के बिना व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या व सुविधा के संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होते हैं।

॥ आदेश ॥

अतः प्रथम दृष्ट्या व सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली